ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
24, **AKBAR ROAD, NEW DELHI**
COMMUNICATION DEPARTMENT

Highlights of Press Briefing **29 November, 2020**

Shri Randeep Singh Surjewala, General Secretary, AICC addressed media at AICC Hdqrs., today

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा – महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा ना कर सकें, उनकी अवहेलना करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। तीन खेती विरोधी काले कानूनों ने मोदी सरकार के मुखौटे को उतार दिया है और देश के 62 करोड़ किसानों और खेत मजदूरों की अवहेलना, विडंबना सरकार का अहंकार तो देखिए, देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह 1,200 किलोमीटर दूर हैदराबाद में चुनावी रैली तो करने जा सकते हैं, पर वो दिल्ली के बॉर्डर पर 15 किलोमीटर दूर जाकर देश के लाखों किसानों से बात नहीं कर सकते।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर लाखों किसानों को, जो दिल्ली के चारों तरफ अपनी रोजी-रोटी मांगने के लिए कराह रहे हैं, उन्हें आतंकी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी आई टी सैल के अमित मालवीय लाखों किसानों को जो अपना अधिकार मांगने आए हैं, उनको आतंकी और खालिस्तानी बताते हैं। मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार मिलकर शांतिप्रिय और गांधीवादी तरीके से अधिकार मांगने वाले हजारों किसानों पर मुकदमें दर्ज कर लेती है। देश के कृषि मंत्री और देश के गृहमंत्री ये तारीख रख देते हैं कि ठिठुरती सर्दी के अंदर सड़कों पर बैठे लाखों किसानों से 3 दिसंबर तक बातचीत भी नहीं होगी। देश के गृहमंत्री, देश के कृषि मंत्री के पास 5-5 दिन तक अहंकारी सरकार के दरवाजे पर दस्तक देकर अधिकार और रोटी मांगने वाले किसान के लिए समय नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने तो हद ही कर दी, गृहमंत्री और कृषि मंत्री किसानों से वार्तालाप का स्वांग करते हैं और आज मन की बात में देश के प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी जी खेती विरोधी तीनों काले कानूनों को सही ठहराते हैं। **जब देश का मुखिया, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी ही इन तीन काले कानूनों के समर्थन में आ खड़े होंगे, तो बातचीत किससे होगी, कैसे होगी और उस बातचीत का फायदा क्या होगा?**

असल में मोदी सरकार का मूल मंत्र है - किसानों का शोषण, पूंजीपतियों का पोषण। किसानों का दमन, पूंजीपतियों को नमन।

आज प्रधानमंत्री, मोदी जी ने मन की बात में अन्नपूर्णा माता की चर्चा की। मोदी जी क्या अन्नपूर्णा की देवी आज कराह नहीं रही होंगी, जब अपने लाखों-करोड़ों, देश के 62 करोड़ उसके बच्चों, किसानों और मजदूरों को सड़कों पर हाहाकार करते हुए देख रही होगी?

सच्चाई ये है साथियों कि मोदी सरकार मुट्ठीभर पूंजीपतियों के पैर पूजने वाली मोदी सरकार 20 से 25 लाख करोड़ के कृषि उपज के व्यापार और कारोबार को 4 या 5 पूंजीपतियों की गोदी में सौंप देना चाहती है। छोटे-छोटे दुकानदारों, आढ़तियों, मजदूरों, बटाईदारों, कामगारों और किसानों के पेट पर लात मारना चाहती है। मोदी जी देश के किसानों द्वारा उठाई जा रही सीधे-सीधे 6 सरल बातों का जवाब देश आपसे मांगता है और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से वो हम आपके समक्ष रखते हैं। जवाब दीजिए-

1. समर्थन मूल्य की समाप्ति के षड़यंत्र के लिए मोदी सरकार ने अनाज मंडियों को खत्म करने का कानून बनाया है। अगर अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी, तो मिनिमम सपोर्ट प्राईस यानि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान का अनाज खरीदेगा कौन? क्या मोदी सरकार और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 15 करोड़ किसानों के खेत से फसल खरीदने जाएंगे? ये अपने आपमें असंभव है। जब समर्थन मूल्य कोई देगा ही नहीं, जो अनाज मंडी में मिलता है, तो फिर एमएसपी यानि समर्थन मूल्य मिलेगा कैसे, देगा कौन और मिलेगा कहाँ? किसान इस बात का जवाब मांगता है?

2. जमाखोरों को खुली छूट क्यों दे दी? इन काले कानूनों में मोदी सरकार ने काला बाजारियों और जमाखोरों को असीमित मात्रा में खाने-पीने की वस्तुओं का भंडारण करने की ताकत दे दी है। यानि अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू नहीं होगा, जो जितना चाहें दालें, सब्जियां, प्याज, गेंहू, धान, बाजरा, सरसों, जौ, उनका भंडारण कर सकता है। जब किसान की फसल बाजार में आएगी, तो औने-पौने दामों पर खरीदी जाएगी और बड़े-बड़े धन्ना सेठ, कालाबाजारिये और जमाखोर उसका भंडारण कर आम जनमानस को अपने मन मर्जी के दामों पर उसे बेचेंगे। सरकार कोई दखलअंदाजी नहीं करेगी, ऐसा क्यों?

3. प्रधानमंत्री, मोदी जी आप एक देश और एक बाज़ार का सफ़ेद झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में फ़सल जाकर बेच सकता है। पर 86 प्रतिशत देश के किसानों के पास तो 5 एकड़ से कम ज़मीन है। उसमें भी 80 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ ज़मीन है। वो अपने जिले से बाहर फसल बेचने में सक्षम नहीं, वो अपनी फसल मंडी तक ले जाकर बेचने में सक्षम नहीं, वो दूसरे राज्यों में कैसे बेचेगा? जवाब सीधा है- धन्ना सेठ, काला बाजार, काला बाजारी और जमाखोर उसकी फसल औने-पौने दामों पर खरीदेंगे और फिर पूरे देश में जहां मर्जी हो वहाँ बेचेंगे।

4. मोदी जी आपने खेती को पूँजीपतियों के हवाले क्यों कर दिया? मोदी सरकार ने कॉरपोरेट कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग का कानून बनाकर एक नई किस्म की जमींदारी प्रथा की शुरुआत की है यानि 86 प्रतिशत जो छोटे किसान हैं, वो खुद के खेत में ही मजदूर बन जाएंगे और कंपनियां उनकी मालिक बन जाएंगी और ना वो उनसे लड़ पाएंगे और ना वो उनसे मुकदमा जीत पाएंगे। 20 से 25 लाख़ करोड़ का खेती का कारोबार, खेती की उपज का कारोबार मुट्ठी भर लोगों के हाथ में चला जाएगा, ऐसा क्यों?

5. गरीब की राशन प्रणाली पर प्रहार क्यों किया और मंडियों के आढ़ती-मजदूर और कर्मचारियों को बेरोजगार क्यों किया? जब समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा ही नहीं जाएगा, तो भोजन के अधिकार कानून में 86 करोड़ देशवासियों को राशन की दुकान पर राशन मिलेगा कैसे और देगा कौन? और यही नहीं लाखों करोड़ों लोग मंडियों में ट्रांसपोर्टर, आढ़ती, दुकानदार, कर्मचारी, मजदूर, इन सबका काम करते हैं, उनके रोटी और रोजगार का क्या होगा?

6. और आखिरी, खेत मज़दूर - बटाईदार का भविष्य अंधकारमय क्यों कर दिया? इन तीनों काले कानूनों में कहीं भी खेत मजदूर और बटाईदार शब्द की चर्चा भी नहीं, वो कहाँ जाएंगे?

और आज मोदी जी ने इन तीन काले कानूनों की चर्चा करते हुए इन्हें सही ठहराते हुए मन की बात में मक्का की फसल की चर्चा कर डाली। आईए जानते हैं मक्का के किसान की हकीकत क्या है -

देश में मक्का पैदा करने वाला किसान बदहाली के आँसू बहा रहा है। मक्का का समर्थन मूल्य है 1,850 रु प्रति क्विंटल और आप बिहार के सीमांचल से मध्यप्रदेश तक चले जाइए, किसान को मिला 800 रुपए क्विंटल, 1,850 रुपए क्विंटल की बजाए। मध्यप्रदेश से बिहार तक, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा और पंजाब में किसान गुहार लगाते रहे पर सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। एक षड़यंत्र के तहत मोदी सरकार मक्का के दाम गिराती रही और हद तो ये देख लीजिए कि मोदी सरकार ने विदेशों से मक्का की फसल की इंपोर्ट ड्यूटी और चौंकिए मत, मोदी जी ने विदेशों से मक्का की इंपोर्ट की जो ड्यूटी है, उसे 50 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया और पाँच लाख मीट्रिक टन सस्ता मक्का विदेश से मंगा लिया, जब देश के किसान का मक्का बाजार में आ रहा था। इस प्रकार से पूंजीपतियों के साथ मिलकर षडंयत्र किया जा रहा है।

हमारा सीधा कहना है कि मोदी जी किसानों के साथ छल कपट और षड़ंयत्र करना बंद कीजिए और पूर्वाग्रह छोड़ इन तीन खेती विरोधी काले कानूनों को खत्म करने के लिए सीधे मन से बात कीजिए। हमारी मांग:-

1. प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी तीनों खेती विरोधी काले कानूनों को फौरी तौर से 'सस्पैंड' करने की घोषणा करें।

2. किसानों के खिलाफ दर्ज 12 हजार एफआईआर बगैर शर्त के फौरी तौर से वापस लेने की घोषणा करें।

3. प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी स्वयं जो उन्होंने आज मन की बात में इन तीन काले कानूनों को सही बताते हुए कहा, उसके लिए और हरियाणा के मुख्यमंत्री, श्री मनोहर लाल खट्टर किसानों को आतंकी बताने के लिए सार्वजनिक तौर से अपना बयान वापस लेते हुए माफी मांगे।

4. प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी स्वयं लाखों किसान जो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, उनके प्रतिनिधिमंडल से बात करें।

श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में हम आश्वस्त हैं कि मोदी सरकार के अहंकार को हराकर हम किसानों की आजीविका को सुनिश्चित करेंगे।

Shri Randeep Singh Surjewala said- Prime Minister's obduracy, Prime Minister's arrogance, Prime Minister's rigidity in dealing with 62 crore farmers and farm labourers of India is writ large by his insistence today in the 'Mann Ki baat' that the three Anti Farmer, Anti Agriculture laws forcibly passed in a illegal and unconstitutional fashion by Parliament are correct. For Prime Minister to say that these three laws are absolutely right, when lakhs and lakhs of farmers are sitting all around Delhi agitating, demanding their withdrawal shows that Modi Government is drunk with power and Prime Minister Shri Narendra Modi does not care about the welfare of farmers and farm labourers of India. It shows that a Government drunk with power is rigid even in re-contemplating and reconsidering the three Anti Agriculture black laws.

If Home Minister of India has time to travel 1,200 kilometres to address a public meeting in Hyderabad, why does Shri Amit Shah not have time to go 15 kilometres to the border of Delhi and speak to the agitating farmers? Why is it that Agriculture Minister has taken out a date of 3rd December before which no conversation can be held? Have they consulted an astrologer for this purpose? What is the sanctity of 3rd December? Why have 12,000 FIRs been lodged on the farmers? Why is it that no conversation is taking place, no dialogue is taking place with the farmers? Why are India's Anndata, India's 62 crore farmers being branded as terrorists by Modi Government as also the BJP Chief Ministers? Why is it that select news channels aided and abetted by Modi Government are out to prove that 62 crore farmers are antinational? Does this not show an absolute arrogance of power on part of Prime Minister and his Government?

On another question about ongoing Hyderabad elections, Shri Surjewala said- I don't think so that is correct at all. Our PCC Presidents, our CLP Leaders, our In-Charges are all on the ground fighting the election and our Units have always fought corporation elections to the best of their capacity and capability and we are confident that people will accept and elect Congress Party in Hyderabad which is the principal opposition party and which carved out the state of Telangana when BJP was opposing the carving out of the state of Telangana itself.

On another question, Shri Surjewala said- The three anti agricultural laws have opened an opportunity for 4 or 5 crony capitalist friends of the Prime Minister to grab the 20-25 lakh crores agriculture commodities market by subverting and subjugating the interest of farmers, farm labourers, the small grain merchants, the labourer work and the employees working in the grain markets across India. It tantamounts to finishing forever the Minimum Support Price Mechanism which will be a death knell for the interest of the farmer. So, Prime Minister wants to barter the interest of 62 crore farmers at the altar of 4 or 5 capitalist friends of his and ensure that 20-25 lakh crore commodity market is now controlled by his 4 or 5 crony capitalist friends, but, Prime Minister has bitten more than he can chew for he does not realize that when 62 crore farmers rise in unison, the Delhi Darbar will be unseated and that is not a warning, that is a challenge to the Prime Minister.

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री सुरजेवाला ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी जी मन की बात में कृषि विरोधी काले कानूनों को सही बताते हैं और देश के गृहमंत्री अमित शाह जी किसानों के पास 15 किलोमीटर चलकर जाने से भी कतराते हैं। अमित शाह जी के पास 1,200 किलोमीटर दूर हैदराबाद में चुनावी सभा तक जाने के लिए समय है, पर ठिठुरती सर्दी में सड़कों पर पड़े कराहते इस देश की माटी के सपूतों, अन्नदाता किसानों से मिलने का समय नहीं। किसानों से बॉर्डर पर जाकर बात क्यों नहीं की जा सकती थी? बुराड़ी में ऐसा क्या है, जो शंभु बॉर्डर पर नहीं हो सकता? ये दर्शाता है और 3 दिसंबर का कौन सा मुहूर्त है बातचीत करने का? क्या किसी ज्योतिषी से अमित शाह जी और नरेन्द्र मोदी जी ने 3 दिसंबर की तारीख निकलवाई है वार्तालाप के लिए? ये दर्शाता है कि मोदी सरकार अहंकार में डूबी है, सत्ता के नशे में चूर है और 20 से 25 लाख करोड़ के कृषि कारोबार को किसान की रोटी छीन मजदूर के पेट पर लात मार, छोटे व्यापारी और आढ़ती का धंधा खत्म कर, मंडी में काम करने वाले मजदूर की रोटी छीन, ट्रांसपोर्टर का व्यापार छीन, कर्मचारी का रोजगार छीन, वो 25 लाख करोड़ के व्यापार को अपने 4-5 दोस्तों को सौंपना चाहते हैं। ये देश की खेती का अपमान है, देश के किसान का अपमान है, जो प्रधानमंत्री, मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं और ये कभी स्वीकार नहीं होगा। वो ये जान लें, इसे चेतावनी मान लें कि जिसने भी देश के 62 करोड़ किसानों की जब-जब दिल्ली के दरबार ने बात नहीं मानी, अपमान किया, हितों की अनदेखी की है, तो उस दरबार का तख्ता पलट हुआ है और मोदी जी अबकी बार लगता है कि बारी आपकी है।

Sd/-
(Dr. Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt,
AICC